(c) the quantity and rates of wheat imported per-annum during the last theee years; and

(d) the action taken by Government to provide the infrastructure to our farmers to increase the production of wheat so that the extra money spent in importing wheat can be saved?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) All India estimates of production of wheat during the last 3 years i.e. 1994-95, 1995-96 and 1996-97 (likely) are 65.77, 62.62 and 64.66 million tonnes respectively.

(b) The per capita net availability of wheat during 1994, 1995 and 1996 has been 159.5, 172.0 and 178.9 gms. per day.

(c) There has not been any import of wheat during 1994-95 and 1995-96. During 1996-97 Government had decided to import upto 2 million tonnes of wheat. Against this a quantity of 16.75 (± 5%) lakh tonnes from Australia, Canada and Argentina has been contracted for import as per details given below:—

Country	Date of Contract	Quantity (lakh MT)	Price US $ (per MT)
Australia	10.12.96	10.00	148.00 FOB
	31.1.97	1.25	156.00 FOB
	14.2.97	2.00	156.00 FOB
Canada	11.12.96	2.50	152.50 FOB
Argentina	4.2.97	1.00	173.00 C&F

(d) The action taken by Government to provide infrastructure to farmers include making available power to farmers, expansion in irrigated area, strengthening of co-operatives for supply of inputs including fertilizers, high yielding varieties/certified seeds and strengthening of agricultural credit.

राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना

3731. **श्री राघवजी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 में सरकार द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इस धनराशि को किन-किन मदों पर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) 1996-97 में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) राजीव गांधी शैक्षिक मिशन योजना नामक कोई भी केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है। हालांकि, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना अनेक राज्यों में कार्यरत है। मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सोसायटी का नाम राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन है। वर्ष 1996-97 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को भारत सरकार द्वारा 83.86 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

(ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राथमिक स्कूलों के लिए मांगों और बुनियादी सुविधाओं के सुधार हेतु प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के घटक निम्नवत हैं:

कक्षाओं और नए स्कूलों का निर्माण।

अनौपचारिक/वैकल्पिक स्कूलों केन्द्रों का खोला जाना।

नये शिक्षकों की नियुक्ति

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण केन्द्रों का गठन।

राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों/जिला शैक्षिणिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों/समूह संसाधन केन्द्रों का गठन।

शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण-अध्ययन सामग्री का विकास।

बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिक्षा, एकीकृत शिक्षा हेतु विशेष हस्ताक्षेप।

अनुसंधान आधारित हस्तक्षेप।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत-राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप जिला-सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग) भारत सरकार राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को छह महीने के अग्रिम आधार पर सामान्यतः वर्ष में दो बार निधियां प्रदान करती है। इसके बाद जिलों में निधियों का वितरण परियोजना की प्रगति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

Importance of Libraries in Literacy Movements

3732. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2173 given in the Rajya Sabha on 14th March, 1997 and state:

(a) whether any financial assistance is being offered to Tamil Nadu in regard thereto; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) An amount of Rs. 7,26,44,000.00 is being considered to be sanctioned to the State Government of Tamil Nadu for being utilised to set up 2,538 Continuing Education Centres and 382 nodal Continuing Education Centres in eight districts namely Kamrajar, Pusumpon Muthuramalinga Thever, Pudukkotai, Kanyakumari, Madurai, South Arcot Ambedkar, Tirunelveli Kattabomman and Ramanathapuram.

Number of SPDAs in Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh

3733. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Sports Project Development Areas (SPDAs) set-up in Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh with locations thereof;

(b) whether Government propose to set-up more SPDAs in these States; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN): (a) The number of Sports Project Devlopment Areas (SPDAs) Set-up in Pubjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh is as under:—

Punjab	—2 (Ludhiana and Patiala)
Tamil Nadu	—2 (Salem and Nagercoil)
Uttar Pradesh	—3 (Safai-Etawah, Rai-Bareilly and Kashipur)

(b) There is no proposal to set-up more SPDAs in these States, for the present.

(c) Does not arise.